नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 269
दि. 31.01.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बात की, दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी का विस्तार और गहराई से विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यह बातचीत वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद हुई।

पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से फोन पर की बात, अमेरिकी दवाब के बीच किन मुद्दों पर बनी सहमति ?

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जनता के बीच संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी का विस्तार और गहराई से विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज ने दोनों देशों के आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और ग्लोबल साउथ के लिए उनके घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक्स

पर एक पोस्ट में कहा, 'मैंने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति, डेल्सी रोड्रिगेज से बात की।' पीएम मोदी ने बताया, 'हम सभी क्षेत्रों में अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा एवं व्यापक बनाने पर सहमत हुए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में भारत-वेनेजुएला संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।'

अमेरिकी दबाव के बीच अहम है यह बातचीत

अमेरिकी दबाव के बीच पीएम मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई यह बातचीत काफी अहम है। इससे भारत-वेनेजुएला के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे, साथ ही भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा में विकल्प बढ़ेगा।

दोनों नेताओं के बीच हुई यह बातचीत ट्रंप के दबाव के बीच भारत की स्वतंत्र कूटनीति का वाशिंगटन को सीधा संदेश है।

अमेरिकी नीतियों का भारत-वेनेजुएला दोनों पर असर

भारत और वेनेजुएला दोनों ही देश इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती नीतियों के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। जहां एक ओर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। वहीं वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना पकड़कर उन्हें न्यूयॉर्क ले गई थी। जिसके बाद से ही वेनेजुएला में टेंशन का माहौल है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल भंडार पर अमेरिका अपना कब्जा करेगा।

डेल्सी रोड्रिगेज ने पांच जनवरी को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला था। यह घटनाक्रम अमेरिकी सेना द्वारा उनके पूर्ववर्ती मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाए जाने के दो दिन बाद हुआ।

लखनऊ में गोमती तट पर सीएम योगी ने किया दीपदान, महात्मा गांधी और अमर शहीदों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

(एजेंसी)।

लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित दीपदान एवं भजन-संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर भजन-संध्या में भाग लेते हुए दीपदान भी किया। उन्होंने महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान गांधीजी के प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम...' में स्वयं शामिल होकर मुख्यमंत्री ने गांधीजी के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के धेमाजी में 10वें 'मिसिंग यूथ फेस्टिवल' को संबोधित किया

(एजेंसी)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के धेमाजी में 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल को संबोधित किया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय मंत्री श्री सवार्नंद सोनोवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मिसिंग यूथ फेस्टिवल ने पूरे देश के ट्राइब्स को एक अलग दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों, संस्कृति, भाषा, साहित्य, नृत्य और संगीत की रक्षा करने का रास्ता हाथ में बंदूक लेकर नहीं बल्कि यूथ फेस्टिवल के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई संस्कृतियों को मिलाकर मिसिंग संस्कृति की तरह ही भारत की संस्कृति बनती है। श्री शाह ने कहा कि यह दृष्टिकोण आज असम को आगे ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊङ्घल्ल८-ढङ्क'ङ्क सिर्फ असम और अरुणाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत को दुनियाभर में प्रसिद्ध बनाती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में अलग अलग जनजातियां अपनी संस्कृतियों की रक्षा के लिए संघर्ष करती थीं और विपक्षी सरकारें इन सभी को कुचल कर रखना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त इंटरलॉक्यूटर सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का मानना है कि हर संस्कृति, भाषा, परंपरा को भारत में जीवित रहने का समान अधिकार है और इन सबके संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि बोगीबील ब्रिज की रचना हमारे मिसिंग श्रमिक भाईयों-बहनों के पसीने से हुई है। यह ब्रिज आज पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का

भाजपा जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने सीएम योगी से मुलाकात की:बागपत के क्षेत्रीय मुद्दों और योजनाओं पर हुई चर्चा

बागपत के भाजपा जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र का गुड़ भेंट किया।

जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के साथ जिले में चल रही प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उन्हें पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाकर लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

भारत संपर्क - देश के युवाओं से संवादः केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आईआईटी दिल्ली में छात्रों से बातचीत की

(एजेंसी)।

आउटरीच पहल 'भारत संपर्क—देश के युवाओं से संवाद' के तहत केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर का दौरा किया और छात्रों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

(दिल्ली स्थित आईआईटी परिसर में छात्रों से बातचीत करते हुए मंत्री महोदय)

इस बातचीत के दौरान छात्रों ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रौद्योगिकी अपनाने, रसद, नवाचार, अनुसंधान सहयोग और सार्वजनिक संस्थानों में युवाओं की भागीदारी के अवसरों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा रूपांतरण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

छात्रों के करियर के अवसरों और सरकारी संस्थानों के साथ प्रत्यक्ष सहभागिता से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नयन और संगठनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने रसद, नागरिक-केंद्रित सेवाओं, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवा वितरण में इंडिया पोस्ट की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया तथा छात्रों को इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट और नवाचार-संचालित सहयोग के माध्यम से विभाग से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।

नवाचार और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास से संबंधित प्रश्नों पर केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट भारत के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स इकोसिस्टम, विशेष रूप से टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आईटी 2.0 आधुनिकीकरण परियोजना और डिजिटल प्रणालियों के तहत नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से इंडिया पोस्ट एक विश्वसनीय, भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक सेवा संस्थान के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया पोस्ट ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और उभरते व्यावसायिक अवसरों के अनुरूप नए, बाजार-संरेखित उत्पाद और सेवाएं भी पेश कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी दिल्ली स्थित अगली पीढ़ी वाले (नेक्स्ट जनरेशन) कैंपस डाकघर का भी दौरा किया, जो देश का पहला डाकघर है और इसे एन-जेन पहल के तहत नया रूप दिया गया है।

भारत पर्व 2026 का समापन समारोह 31 जनवरी 2026 को होगा

पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने स्थित लॉन और ज्ञानपथ पर भारत पर्व का आयोजन करता है।

भारत पर्व 2026 का समापन समारोह 31 जनवरी 2026 को शाम 5:30 बजे होगा। उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे।

भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एनसीडब्ल्यू स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया

(एजेंसी)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा और समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा ने मुख्य भाषण देते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और इस बात पर बल दिया कि महिलाओं का सशक्तिकरण भारत के समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की 34 वर्षों की यात्रा यह दशार्ती है कि संस्थाएं केवल कानून बनाने से ही नहीं, बल्कि महिलाओं से संबंधित जटिल मुद्दों के समाधान में अपनी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और निरंतर प्रयासों से मान्यता प्राप्त करती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य नीति में आए व्यापक बदलाव पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने मुख्य रूप से उपचारात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक निवारक एवं संवर्धक स्वास्थ्य सेवा मॉडल को अपनाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने निवारक, संवर्धक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, देश भर में 1.81 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जो 1.4 अरब से अधिक नागरिकों की सेवा कर रहे हैं।

दक्षिण कोरिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश से मुलाकात की

(एजेंसी)।

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष श्री ली हैक-यंग के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद भवन में राज्यसभा उपाध्यक्ष श्री हरिवंश से मुलाकात की।

बैठक के दौरान श्री हरिवंश ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया सशक्त और प्रगतिशील लोकतंत्र हैं और संसदीय आदान-प्रदान की एक

मजबूत परंपरा साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संसदों के बीच नियमित संवाद और बातचीत ने भारत-कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

द्विपक्षीय सहयोग के बहुआयामी स्वरूप पर श्री हरिवंश ने कहा कि भारत और कोरिया व्यापार और निवेश, रक्षा, संस्कृति और जन-जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी साझा करते हैं। यह लोकतंत्र, कानून के शासन, वैश्विक शांति और समृद्धि के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।

दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करते हुए, श्री हरिवंश ने कहा कि भारत और कोरिया अयोध्या की राजकुमारी सुरिरत्ना और गिम्हे के राजा किम सूरो के बीच वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

गणतंत्र दिवस-2026 की परेड में संस्कृति मंत्रालय की 'वंदे मातरम - 150 वर्षों का सफर' नामक झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता

सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति 'वंदे मातरमः भारत की शाश्वत गूंज' को मिला विशेष पुरस्कार

(एजेंसी)।

गणतंत्र दिवस परेड-2026 में संस्कृति मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण दोहरा सम्मान प्राप्त किया, जहां उसकी "वंदे मातरम - 150 वर्षों का सफर" शीर्षक वाली झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वहीं उसकी भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति "वंदे मातरमः भारत की शाश्वत गूंज" को उसकी असाधारण कलात्मक और विषयगत उत्कृष्टता के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार विजेता झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्षों के सफर को सशक्त रूप से दशार्या, जिसमें राष्ट्रीय जागरण के गीत के रूप में इसके उद्भव और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, एकता और सभ्यतागत चेतना को आकार देने में इसकी स्थायी भूमिका को दिखाया गया है। भावपूर्ण दृश्यों और प्रतीकों के माध्यम से, झांकी ने भारत की सामूहिक राष्ट्रीय पहचान में राष्ट्रगान की शाश्वत प्रासंगिकता को उजागर किया।

विशेष पुरस्कार विजेता सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति, 'वंदे मातरम - भारत की शाश्वत गूंज', का आयोजन संगीत नाटक अकादमी ने पटियाला स्थित उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से किया था। यह प्रस्तुति राष्ट्रऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर बनी। इस प्रस्तुति में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,500 कलाकारों ने भाग लिया और शास्त्रीय, लोक और आदिवासी कला रूपों के माध्यम से देश की विशाल सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया।

नृत्य प्रस्तुति ने देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और सशस्त्र बलों के शौर्य और समर्पण तक की शाश्वत यात्रा को जीवंत कर दिया। संस्कृत मंत्रों, भावपूर्ण संगीत और गतिशील नृत्य संरचनाओं से परिपूर्ण इस प्रस्तुति ने वंदे मातरम के संपूर्ण भावनात्मक और दार्शनिक पहलू को समाहित किया, जिसका समापन एकता, भक्ति और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हुआ।

संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा ने समग्र रचनात्मक निर्देशक के रूप में सांस्कृतिक प्रस्तुति का नेतृत्व किया।

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री 2026-27 के केंद्रीय बजट के बाद पूरे भारत के युवाओं के साथ संवाद करेंगी

2026-27 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 30 कॉलेज छात्रों के साथ संवाद करेंगी।इस पहल के हिस्से के रूप में, कॉलेज छात्र लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट की

लाइव प्रस्तुति को देखने का अवसर प्राप्त करेंगे, जो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाहियों में से एक है। ये छात्र वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और विभिन्न राज्यों से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विविध शैक्षणिक अनुशासनों से हैं।

छात्र वित्त मंत्रालय का भी दौरा करेंगे, जो कर्तव्य भवन-1 में स्थित है, वहां ये विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे ताकि मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया तथा राष्ट्र निर्माण में संस्थाओं की भूमिका को समझ सकें।

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को विधिवत संभालते हुए

महाप्रबंधक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे : श्री प्रदीप कुमार

मुंबई, 30 जनवरी, 2026

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार 29 जनवरी, 2026 से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री प्रदीप कुमार भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा (IRSME) के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको भारतीय रेल में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

अपने सेवाकाल के दौरान आपने पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे (SER), ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) सहित विभिन्न जोनल रेलों पर महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार पदों पर कार्य किया है।

श्री प्रदीप कुमार ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं, जिनमें कैरिज वर्कशॉप, अजमेर में प्रोडक्शन इंजीनियर; कोटा में मंडल यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज एवं वैगन); वडोदरा में मंडल यांत्रिक इंजीनियर; पश्चिम रेलवे में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (योजना), उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (वर्कशॉप) तथा मुंबई के कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने कोटा के वैगन रिपेयर शॉप में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (मरम्मत) तथा वरिष्ठ ईडीपीएम के रूप में भी कार्य किया है।

श्री कुमार ने कई महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी पदों पर भी कार्य किया है, जिनमें दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता में मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर; भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान (IRIMEE), जमालपुर में वरिष्ठ प्रोफेसर; ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी के पद शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा विरार-सूरत-वडोदरा खंड पर कवच 4.0 का कमीशन

मुंबई, 30 जनवरी, 2026

यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए पश्चिम रेलवे ने 344 किलोमीटर लंबे विरार-सूरत-वडोदरा खंड पर यात्री ट्रेनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन संरक्षण प्रणाली कवच संस्करण 4.0 को कमीशन कर दिया है। 30 जनवरी, 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई, जब ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस मुंबई से चलने वाली पहली कवच-सुसज्जित ट्रेन बनी। यह पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विरार-सूरत-वडोदरा खंड के 344 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कवच प्रौद्योगिकी को कमीशन किया गया है। इस कॉरिडोर पर कवच को 49 स्टेशनों पर लागू किया गया है, जिसे 57 रेडियो संचार टावरों तथा लगभग 700 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का सहयोग प्राप्त है। कवच एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, जो सिगनल का खतरे की स्थिति में पार होना, अधिक गति तथा टक्करों जैसी मानवीय त्रुटियों से उत्पन्न जोखिमों को न्यूनतम करने में सहायक है। साथ ही, लेवल क्रॉसिंग पर स्वचालित सीटी (ऑटो-व्हिसलिंग) और लोको पायलट के केबिन में सिगनल पहलू की पुनरावृत्ति जैसी विशेषताओं के माध्यम से प्रतिकूल मौसम और कम दृश्यता की परिस्थितियों में भी परिचालन सुरक्षा को और सुदृढ़ करता है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (कार्यवाहक) श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दादर (पश्चिम रेलवे) स्टेशन पर कवच संस्करण 4.0 के कमीशनिंग के अवसर पर। (दाएँ) ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सायाजीनगरी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव में स्थापित कवच उपकरण। दाहिने तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रणाली के कार्य-प्रणाली का व्याख्यात्मक चित्र, जिसमें स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के लिए ऑनबोर्ड, ट्रैकसाइड तथा स्टेशन-स्तरीय घटकों के निर्बाध एकीकरण को दशार्या गया है।

पश्चिम रेलवे द्वारा इससे पूर्व दिसम्बर 2025 में वडोदरा-अहमदाबाद खंड पर कवच प्रणाली को कमीशन किया गया था। विरार-वडोदरा खंड के कमीशन होने के साथ ही, वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर कुल 435 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है।

श्री विनीत ने आगे कहा कि भारतीय रेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रौद्योगिकी एक तकनीकी रूप से उन्नत एवं लागत-प्रभावी सुरक्षा समाधान है, जो रेलवे सुरक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है।

पहले से कमीशन किए गए खंडों के अतिरिक्त, पश्चिम रेलवे के 2667 रूट किलोमीटर को कवर करने वाले अन्य कई खंडों पर कवच कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹1435 करोड़ है। इसके अलावा, 2476 मार्ग किलोमीटर पर कवच कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किए गए हैं, जो इस कार्यक्रम के व्यापक स्तर और तीव्र गति को दशार्ते हैं। चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ, पश्चिम रेलवे अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क पर कवच के विस्तार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे समग्र रेल

इंडिया एनर्जी वीक (क्र्ह)2026 का समापनः भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा नेतृत्व की मजबूत पुष्टि और नवाचार उत्कृष्टता की मान्यता

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की तैयारियों, लचीलापन और बढ़ते वैश्विक ऊर्जा प्रभाव को रेखांकित किया

(एजेंसी)।

भारत ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में निरंतर भू-राजनीतिक अस्थिरता का सामना करने के लिए मजबूत तैयारियां प्रदर्शित की हैं और वैश्विक ऊर्जा संवाद के केंद्र में दृढ़ता से बने रहने का संकल्प लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक (क्र्ह) 2026 के समापन समारोह में ये बात कही।समापन फायरसाइड चैट के दौरान बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि भारत की ऊर्जा रणनीति विविधीकरण, लचीलापन और भविष्योन्मुखी संक्रमण पर आधारित है। 'भारत ने लगातार भू-राजनीतिक झटकों का बहुत अच्छे से सामना किया है। श्री पुरी ने कहा कि आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण और स्वच्छ ईंधनों की ओर तेजी से संक्रमण के माध्यम से,' हर चुनौती को अवसर में बदल दिया गया है— भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को रेखांकित करते हुए, उन्होंने नोट किया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है।

उन्होंने जोड़ा 'भारत वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी ऊर्जा की उपलब्धता, किफायतीपन और स्थिरता सुनिश्चित करता रहेगा,' ।

मंत्री के बाद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की 7 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए सरकार की रूपरेखा का वर्णन किया। उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को मजबूत करने पर जोर दिया, साथ ही भारत को परिष्कृत उत्पादों का विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने पर भी। डॉ. मित्तल ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में संचालन दक्षता और लचीलापन सुधारने में डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लॉजिस्टिक्स अनुकूलन की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया।

समापन दिवस पर क्र्ह 2026 का समापन भी चिह्नित किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स, अकादमिया और उद्योग में नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और नेतृत्व को मान्यता देने वाले पुरस्कार प्रदान किए गए।

अविन्या – द एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज के तहत, मिनीमाइन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस विजेता के रूप में उभरा,

ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देने वाले पुरस्कारों के साथ भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का समापन

स्वच्छ ऊर्जा, अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में योगदान के लिए प्रतिनिधियों और नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया गया

(एजेंसी)।

भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में देश के ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाले नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। 27 से 30 जनवरी, 2026 तक गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन ने वैश्विक ऊर्जा इकोसिस्टम में भारत की केंद्रीय भूमिका को उजागर किया, साथ ही नीति निमार्ताओं, व्यापार जगत, नवप्रवर्तकों और निवेशकों को एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा भविष्य के लिए व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट किया।

अविन्या – ऊर्जा स्टार्टअप चुनौती

अविन्या चैलेंज ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करने वाले उभरते भारतीय स्टार्टअप्स को मान्यता दीः

विजेताः मिनिमिन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस – श्री हार्दिक और श्री अनुपम कुमार को एचएचएम प्रक्रिया के लिए सम्मानित किया गया है, जो ईओएल वाली लिथियम-आयन बैटरियों से उच्च-मूल्य वाली सामग्रियों की कम कार्बन वाली रिकवरी प्रदान करती है, और इसका सौर पैनलों, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स और स्थायी चुंबकों में विस्तार जारी है।

प्रथम उपविजेताः ओसस बायोरेन्यूएबल्स – डॉ. सुरुचि राव, श्री कमर सुहैल बाशा, औद्योगिक अपशिष्ट जल को हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करने की उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया के लिए।

द्वितीय उपविजेताः ट्रान्जमेओ आईटी सॉल्यूशंस – श्री सफिल सनी, श्री राकेश मिश्रा, जिन्होंने एआई-संचालित फाइबर-सेंसिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से पाइपलाइनों, वेंट और सीसीयूएस प्रक्रियाओं की सटीक निगरानी को सक्षम बनाया।

तीसरा उपविजेताः रेजलिटिक्स टेक्नोलॉजीज – श्री दीपशंकर नंदा, श्री विनय भारद्वाज, जिन्होंने एआई-संचालित डीप इन्फॉर्मेशन मैक्सिमाइजेशन इंजन विकसित किया है जो तेल और गैस अन्वेषण में क्रांति ला रहा है।

चौथा उपविजेताः पेट्रोबोट टेक्नोलॉजीज – श्री साहब गुर्जर, श्री शशि फागना, हाइड्रोकार्बन संयंत्रों और जहाजों में रोबोटिक निरीक्षण समाधान के लिए।

वसुधा – ओवरसीज अपस्ट्रीम स्टार्टअप चैलेंज

इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ने अपस्ट्रीम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप्स को मान्यता दीः

ॅ३३स्र२://२३३.स्रु.ॅङ्म५.ल्ल/ह१३ी फींङ्किं/४रीथ्र ी२/ी003टफ्ठद.स्रॅ

विजेताः सेनेर्जेटिक्स, नीदरलैंड्स – श्री फ्रांसिस्कस जोहाना जैकब्स, सुश्री अनीता, एआई-संचालित संक्षारण निगरानी के लिए, जो सुरक्षित और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करती है।

उपविजेताः रेसरमाइन इंक, यूएसए – श्री एंटोन माल्कोव, श्री अमित कुमार, जलाशय इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो को अनुकूलित करने वाले हॉकआई हाइब्रिड मॉडल इंजन के लिए।

हैकाथॉन चैलेंज

इसमें सात प्रमुख संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें ऊर्जा प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषी समस्या-समाधान को मान्यता देने वाले पुरस्कार शामिल थेः

ॅ३३स्र२://२३३.स्रु.ॅङ्म५.ल्ल/ह१३ी फींङ्किं/४रीथ्र ी२/ी004192.स्रॅ

विजेताः आईआईटी बॉम्बे – सौतिक भक्ता, प्रोफेसर कुमार हेमंत सिंह, जिन्होंने ऑरा नामक एक एआई-संचालित एकीकृत जलाशय विश्लेषण मंच विकसित किया है, जो अर्ध-पर्यवेक्षित सीएनएन ट्रांसफार्मर फ्रेमवर्क का उपयोग करता है।

उपविजेताः आईआईटी दिल्ली – स्वागत सब्यसाची साहू, अक्षत अग्रवाल, मनोग्या सुनील चोरडिया, देबरुन बनर्जी, प्रोफेसर विक्रांत, जिन्होंने इस्पात उद्योग के स्लैग के माध्यम से द्वि-क्षारीय विलायक-आधारित सीओ$_2$ कैप्चर और खनिजकरण का उपयोग करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण अपनाया।

एफआईपीआई / आईआईपी वार्षिक उद्योग पुरस्कार

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ ने अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, नवाचार और गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता

रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार प्रदान किए

26 जनवरी का दिन विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति राष्ट्र के संकल्प की पुष्टि करता हैः श्री संजय सेठ

(एजेंसी)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 30 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस परेड-2026 के अंतर्गत तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/अन्य सहायक बलों की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा राज्य मंत्री ने परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को बधाई दी और इस बात पर बल दिया कि 26 जनवरी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति राष्ट्र के संकल्प की पुनः पुष्टि का प्रतीक है। रक्षा राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री की उस अपील को भी दोहराया, जो पीएम एनसीसी रैली-2026 के दौरान युवाओं से की गई थी, जिसमें प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित करने और किसी चयनित स्थान पर गतिविधि आयोजित करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने स्वच्छता को पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

टुकड़ियों एवं झांकियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए गठित तीन न्यायाधीश पैनलों द्वारा निम्नलिखित टुकड़ियों और झांकियों का चयन किया गयाः

- तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता – भारतीय नौसेना
- सीएपीएफ/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता – दिल्ली पुलिस
- शीर्ष तीन झांकियां (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश):

महाराष्ट्र (गणेशोत्सवः आत्मनिर्भरता का प्रतीक)

2. जम्मू – कश्मीर (जम्मू – कश्मीर के हस्तशिल्प एवं लोक नृत्य)

3. केरल (वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरताः आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल)

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी – संस्कृति मंत्रालय (वंदे मातरम – राष्ट्र की अन्तरात्मा की पुकार)

विशेष पुरस्कारः

1. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (वंदे मातरम – 150 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव)
2. 'वंदे मातरमः भारत की शाश्वत गूंज' नृत्य समूह

नागरिकों द्वारा अपनी पसंदीदा झांकी और परेड दस्ते के लिए मायगॉव पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन मतदान के आधार पर 'लोकप्रिय पसंद' श्रेणी के परिणाम इस प्रकार हैंः

- तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता – असम रेजिमेंट

भारत भू-राजनीतिक बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार

इंडिया एनर्जी वीक 2026 का समापन, भारत ने ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में अपनी भूमिका को और मजबूत किया

भारत भू-राजनीतिक बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार है और ग्लोबल एनर्जी डायलॉग में केंद्र में बना हुआ हैः केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी

घरेलू खोज, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और स्थिर कीमतें भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करती हैं

(एजेंसी)।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2026 के समापन समारोह में कहा कि भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में लगातार भू-राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत तैयारी दिखाई है और इंटरनेशनल एनर्जी डायलॉग में केंद्र में बना रहेगा। यह कार्यक्रम 27 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 तक गोवा में आयोजित किया गया।

समापन फायरसाइड चैट के दौरान बोलते हुए, श्री पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एनर्जी रणनीति विविधीकरण, सशक्तता और भविष्य के अनुकूल बदलावों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने लगातार भू-राजनीतिक झटकों का बहुत अच्छे से सामना किया है। सप्लाई के सोर्स के विविधीकरण और क्लीनर फ्यूल की ओर तेजी से बदलाव के जरिए हर चुनौती को एक अवसर में बदला गया है।"

भारत के वैश्विक रुख से अवगत कराते हुए, श्री पुरी ने कहा कि आज देश तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। श्री पुरी ने कहा, "ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी, भारत एनर्जी की उपलब्धता, किफायती दाम और सततता सुनिश्चित करता रहेगा।"

केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक ईंधनों में लगातार निवेश के साथ-साथ कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन और स्वदेशी क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी पर सरकार द्वारा जोर दिये जाने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "पारंपरिक एनर्जी जरूरी रहेगी, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर सीबीजी, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल तक हम जो कदम उठा रहे हैं, वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि ग्रीनर फ्यूल एक बड़ी भूमिका निभाएंगे।"

वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए, श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को अस्थिरता से सफलतापूर्वक बचाया है। उन्होंने कहा, "वैश्विक उथल-पुथल का असर कभी भी उपभोक्ता पर नहीं पड़ा। आज भारत में एनर्जी की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं और संकट के समय भी बिना किसी रुकावट के आपूर्ति बनाए रखी गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा समय पर कार्रवाई के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि एलपीजी सहित फ्यूल की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनी रहें।"

श्री पुरी के बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की विकास यात्रा को समर्थन करने के लिए

भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए कवच 4.0 का विस्तार तेज किया, तीन खंडों में 472 किमी मार्ग पर शुरूआत

एक ही दिन में कवच की अब तक की सबसे बड़ी कमीशनिंग हासिल की गई

वडोदरा-विरार (344 किमी), तुगलकाबाद जंक्शन केबिन-पलवल (35 किमी) और मानपुर-सरमतनार (93.3 किमी) खंडों पर कवच 4.0 की शुरूआत हुई

कवच 4.0 अब भारतीय रेलवे के पांच जोन में 1,300 से अधिक रूट किलोमीटर को कवर करता है

(एजेंसी)।

भारतीय रेलवे ने आज अपने नेटवर्क के तीन खंडों में 472.3 रूट किलोमीटर पर कवच वर्जऩ 4.0 (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) की शुरूआत की, जो रेल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और

महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नए कमीशन किए गए खंडों में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा-विरार (344 किमी), उत्तर रेलवे पर तुगलकाबाद जंक्शन केबिन-पलवल (35 किमी) और पूर्व मध्य रेलवे पर मानपुर-सरमतनार (93.3 किमी) शामिल हैं। इस शुरूआत के साथ, भारतीय रेलवे उच्च-घनत्व वाले मार्गों पर ट्रेन सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कवच प्रणाली की तैनाती को तेज करना जारी रखे हुए है।

यह उपलब्धि एक ही दिन और साथ ही एक महीने में कवच कमीशनिंग के अब तक के सबसे अधिक रूट किलोमीटर का रिकॉर्ड है, जिसमें 472.3 आर किमी को कवच वर्जऩ 4.0 के दायरे में लाया गया है। इससे पहले सबसे बड़ी कमीशनिंग पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा-मथुरा खंड पर 324 आर किमी थी। इस

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशाखापत्तनम में 32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीएसआईआर-एनआईओ के तटवर्ती क्षेत्रीय केन्द्र का उद्घाटन किया

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशाखापत्तनम में 32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीएसआईआर-एनआईओ के तटवर्ती क्षेत्रीय केन्द्र का उद्घाटन किया

यह परियोजना 20 वर्षों तक विलंबित रही, लेकिन राज्य में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही पूरी हो गई; इस प्रकार यह 'दोहरे इंजन के प्रभाव' का प्रमाण हैः केन्द्रीय मंत्री

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'नीली अर्थव्यवस्था' और समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दिए जाने पर प्रकाश डाला

सीएसआईआर-एनआईओ की नई सुविधा से भारत के समुद्री विज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा और तटीय सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलेगाः डॉ. जितेंद्र सिंह

सीएसआईआर-एनआईओ का विशाखापत्तनम केन्द्र अपतटीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु संबंधी अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

पूर्वी महाद्वीपीय सीमांत से संबंधित अनुसंधान से तेल, गैस और समुद्री खनिजों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होगीः डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रविष्टि तिथिः 30 खअठ 2026 5:20ढट८ ढक्ह ऊे

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज विशाखापत्तनम स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) के क्षेत्रीय केन्द्र की तटवर्ती प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और इसे 'दोहरे इंजन वाली सरकार के प्रभाव', जहां केन्द्र और राज्य के बीच का निर्बाध समन्वय विकास को गति देता है, का स्पष्ट उदाहरण बताया।

आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री श्रीमती

अनीता वंगलपुडी, सांसद श्री एम. श्रीभरत, विधायक श्री जी. श्रीनिवास राव, सीएसआईआर-एनआईओ के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, डॉ. वी.वी.एस.एस. शर्मा और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. कलैसेल्वी की उपस्थिति में सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही इस परियोजना की नींव वर्षों पहले रखी गई थी, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारों के एकमत होने के बाद पिछले 8-10 महीनों में इसमें काफी प्रगति हुई और यह पूरी हो गई।

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा 2000 के दशक के आरंभ में नाममात्र की कीमत पर हस्तांतरित की गई थी और इस क्षेत्र में हुए तीव्र विकास के कारण इसका वर्तमान मूल्य कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, सीएसआईआर और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (जो सीएसआईआर के अध्यक्ष हैं) की ओर से, कुल 32 करोड़ रुपये की इस तटवर्ती परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रही है।

इस सुविधा के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की तटरेखा लगभग 11,000-12,000 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 1,000 किलोमीटर से अधिक आंध्र प्रदेश से लगती है, जो इसे समुद्री अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री के 'नीली अर्थव्यवस्था' से संबंधित विजन का एक स्वाभाविक केन्द्र बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वी तटीय सीमांत भूवैज्ञानिक रूप से विविधतापूर्ण है और इसमें मुख्य रूप से हिमालयी नदी प्रणालियों द्वारा भारी मात्रा में निक्षेपित हाइड्रोकार्बन, समुद्री खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस की अपार संभावनाएं हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम तट एक बहुमुखी समुद्री संसाधन आधार का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और नव उद्घाटित सीएसआईआर-एनआईओ सुविधा इस प्रयास के एक प्रमुख वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य करेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीएसआईआर-एनआईओ पहले से ही ओएनजीसी, ऑयल इंडिया तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है और फार्मास्युटिकल्स, बंदरगाहों, तापीय ऊर्जा परियोजनाओं व मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि संभावित मछली पकड़ने वले क्षेत्रों की पहचान, मछुआरों के लिए समुद्री शैवाल की खेती और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की भविष्यवाणी करने से संबंधित केन्द्र सरकार के कार्यों से आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ हो रहा है, क्योंकि समुद्री जैव संसाधनों का उपयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

महाराष्ट्र की राजनीति में अब हो सकता है मराठा राजनीति का उभार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को विमान दुर्घटना में मौत से जहां पूरा देश स्तब्ध है, शोक में डूबा हुआ है वहीं यह भी प्राश्न उठ रहा है कि उनकी अकस्मात मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? 66 साल के अजीत पवार का निजी विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करते समय दुर्घटनाग्रास्त हो गया।

बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रोस पाटा (एनसीपी) से बगावत कर दी थी।

2023 में 2 जुलाई को वे अपनी पाटा के 8 सदस्यों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे और सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिदे सरकार में शामिल होने के अपने पैसले पर अजीत पवार ने कहा था, प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रागति कर रहा है, इसलिए भाजपा के साथ वुछ मतभेद होने के बावजूद एनसीपी ने महाराष्ट्र की प्रागति के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाने का पैसला किया है। नवम्बर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और अजीत पवार अपने चाचा पर भारी पड़े। हालांकि छह महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पाटा को केवल एक सीट पर ही जीत मिली थी। तब अजीत पवार को महाराष्ट्र की सत्तारुढ़ भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में अजीत पवार सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने 41 विधानसभा सीटें हासिल की और लगभग अपने चाचा के विद्रोही गुट एनसीपी (एसपी) को खत्म कर दिया। जो केवल 10 सीटें ही जीत सकी। अजीत पवार ने 5 दिसम्बर 2024 को रिकार्ड छठी बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विश्लेषक कहते हैं कि शरद पवार की छाया में 20 साल बिताने के बाद अजीत पवार को लगा कि चाचा उनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं इसलिए उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ़ लिया। 5 फरवरी से महाराष्ट्र जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के प्रचार के लिए अजीत दादा पवार बारामती जा रहे थे। एनसीपी का पूरा दायित्व अजीत पवार के ऊपर ही था। अजीत पवार का निधन तब हुआ है, जब शरद पवार राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। जिला परिषद के चुनाव में अजीत अपने चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे।

अब मुझे लग रहा है कि पूरी सहानुभूति शरद पवार के साथ जाएगी।

भाजपा के उभार के बाद से महाराष्ट्र में मराठा नेताओं की हैसियत कमजोर हुई है और इसका अहसास प्रदेश में सबको है। मराठा जाति का वर्चस्व खेती, शिक्षा और बैंकिग पर खत्म हो चुका है। शरद पवार के साथ अब मराठा जाति की सहानुभूति आएगी। ग्रामीण महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर अब भी मराठा जाति की पकड़ है और इन्हें अब लग रहा है कि भाजपा के आने से उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है।

देवेन्द्र फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी अगर इस सरकार से हट जाती है तब भी सरकार पर कोई फर्व नहीं पड़ेगा। भले सरकार सत्ता में बनी रहेगी लेकिन फर्व दूसरी तरह से पड़ेगा। मराठा जाति अजीत पवार के निधन के बाद सोचेगी कि अब उनके पास कौन है? शरद पवार खुद ही जीवन के सांध्य काल में हैं। पूरा मराठा तबका अब सोचेगा कि उन्हें किस तरफ रुख करना है? एक विश्लेषक का कहना है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हिन्दुत्व के बढ़ते प्राभाव के बीच अपनी ताकत बनाए हुए थे और यह बड़ी बात थी। भाजपा और शिवसेना दोनों हिन्दुत्व की राजनीति करते हैं। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार स्थिर रहेगी लेकिन मराठा राजनीतिक का उभार हो सकता है। एनसीपी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट हो सकती है और यह भाजपा की मजबूती के हक में नहीं होगी। अजीत पवार को देवेन्द्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिदे की शक्ति संतुलन करने के रूप में भी देखा जाता था।

स्वराज की विचारधारा आज राष्ट्र निर्माण के संकल्प की प्रेरणास्त्रोत बनी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

राज्य के 2666 गाँवों को मिलेगा अपना ग्राम पंचायत घर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करने का समारोह आयोजित हुआ

गुजरात की सभी ग्राम पंचायतों को उनका अपना पंचायत घर देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सेचुरेशन के विचार को साकार कराने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री ने आणंद के भादरण से 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' लॉन्च की

पंचायत मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा की प्रेरक उपस्थिति

तहसील मुख्यालय हो और नगर पालिका न हो; ऐसे 114 गाँवों को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के प्रथम चरण में समाविष्ट किया जाएगा, ऐसे गाँवों को शहरी समकक्ष सुविधा मिलने से उनका गुणात्मक एवं सर्वांगीण विकास होगा

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- आगामी समय में राज्य की 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों तक 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के विस्तार का लक्ष्य
- इस योजना के जरिये ग्रामीण एवं शहरी विकास के बीच 'समग्र तथा संतुलित' विकास का विजन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से साकार होगा
- महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की विचारधारा आज राष्ट्र निर्माण के संकल्प की प्रेरणास्रोत बनी है

गांधीनगर, 30 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को आणंद के भादरण में आयोजित समारोह से राज्य की 2666 ग्राम पंचायतों के लिए उनके अपने ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों का एक साथ एक ही स्थान से ई-शिलान्यास करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो फोकस किया है, उसमें गुजरात अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का दिया गया सेचुरेशन अप्रोच गुजरात में साकार करने के लिए राज्य

सरकार ने आगामी दिवसों में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को उनके अपने पंचायत घर-सह-पटवारी आवास देने का महत्वाकांक्षी निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन 2666 गाँवों में कुल 663 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ग्राम पंचायत घर-सह-पटवारी आवासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर से ही सरकारी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी।

उन्होंने इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' की राज्यव्यापी लॉन्चिंग भी की।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के 114 तहसील मुख्यालयों वाले ऐसे गाँव, जो तहसील मुख्यालय हैं; लेकिन नगर पालिका नहीं हैं, को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के प्रथम चरण में समाविष्ट कर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पानी, स्वच्छता, सोलर स्ट्रीट लाइट, ई-ग्राम, कम्युनिटी हॉल आदि शहरी समकक्ष आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने जोड़ा कि शहरों पर बोझ कम हो तथा शहरों जैसी सुविधाएँ गाँवों में मिलें; इस आशय से आगामी समय में राज्य में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' अंतर्गत लाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी विकास के बीच अंतर घटेगा तथा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का प्रधानमंत्री का मंत्र समग्र एवं संतुलित विकास से साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकास की राजनीति को गति देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास का स्केल व स्पीड बढ़े हैं। शहरों में बढ़ते शहरीकरण के दबाव को संतुलित करने के लिए ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों के उत्थान के लिए केन्द्रित ऐसा कार्यक्रम राज्य में पहली बार आयोजित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत वर्षा जल संचय तथा भूमिगत जल रिचार्ज के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हर विधायक को 50 लाख रुपए का विशेष अनुदान आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रिचार्जिंग व्यवस्थाएँ की जा सकें। मुख्यमंत्री ने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि अपनाने की अपील करते हुए सभी से भूमि का स्वास्थ्य सुधारने तथा भावी पीढ़ी को निरोगी भविष्य देने का संकल्प लेने को कहा।

30 जनवरी शहीद दिवस तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण

वर्षांत समीक्षा- 2025: डिजिटल न्याय, उपभोक्ता विश्वास और गुणवत्ता को बाजार में बढ़ावा देना

प्रमुख सुधार और उच्च प्रभाव वाली पहलें

(ई-जागृति, एनसीएच, बीआईएस मानक, कानूनी मेट्रोलॉजी सुधार)

ख. क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण

(एनटीएच, जागरूकता, मूल्य निगरानी, अवसंरचना)

प्रविष्टि तिथिः 30 खअठ 2026 4:29ढट्ु८ ढक्ष ऊै

वर्ष 2025 के दौरान देश में उपभोक्ता संरक्षण ने गति, सुगमता और विश्वास की दिशा में निर्णायक प्रगति की इसलिए उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए एक निर्णायक दौर रहा। व्यापक डिजिटल परिवर्तन, बाजार स्थिरीकरण उपायों, आधुनिक मानकों और मजबूत संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से, विभाग ने उपभोक्ता कल्याण को भारत के विकसित होते बाजार के केंद्र बना रहना सुनिश्चित किया।

इस वर्ष कागज रहित उपभोक्ता अदालतों और एआई-सक्षम शिकायत निवारण से लेकर सुरक्षित घरेलू उत्पादों, सटीक व्यापार प्रथाओं और विस्तारित परीक्षण बुनियादी ढांचे तक, प्रतिक्रियात्मक विनियमन से उत्तरदायी, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन की ओर बदलाव देखने को मिला।

2025 पर एक नजर

ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर 2.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं।

1.31 लाख से अधिक उपभोक्ता मामलों का निपटारा डिजिटल माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से 27.61 करोड़ रुपये की राशि रिफंड की गई। देशभर में 575 केंद्रों पर दैनिक मूल्य निगरानी। कानूनी मापन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 12 जीएटीसी प्रमाणपत्र जारी किए गए। उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए बीआईएस मानक जारी किए गए। उपभोक्ता न्याय का डिजिटल रूपांतरण

ई-जागृतिः गति, सरलता और सुलभताए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में 1 जनवरी 2025 को ई-जागृति का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया। यह एक देश में उपभोक्ता विवाद समाधान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एकीकृत, संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सीओएनएफओएनईटी, ई-दाखिल, ओसीएमएस और एनसीडीआरसी-सीएमएस जैसी पुरानी प्रणालियों को एकीकृत करके, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही इंटरफेस के तहत निर्बाध डिजिटल फाइलिंग, सुनवाई, केस प्रबंधन और निर्णयों को संभव बनाया गया है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई ई-जागृति ने बहुभाषी पहुंच, ओटीपी आधारित पंजीकरण, एन्क्रिप्टेड दस्तावेज आदान-प्रदान, वर्चुअल सुनवाई, वॉयस-टू-टेक्स्ट सहायता और वास्तविक समय में केस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्लेटफॉर्म के शुरू होने से व्यक्तिगत रूप से अदालतों में जाने, मुकदमेबाजी की लागत और प्रक्रियात्मक देरी को काफी कम हो गई है और इससे दूरदराज के स्थानों और विदेशों से भी उपभोक्ता न्याय सुलभ हो गया।

नवंबर 2025 के मध्य तक, 1,400 अनिवासी भारतीयों सहित 2.81 लाख से अधिक उपयोगकताओं ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया था, और अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से शिकायतें दर्ज की गई थीं। 1.35 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और 1.31 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। यह उपभोक्ता आयोगों में त्वरित निपटारे और लंबित मामलों में कमी को दशार्ता है।

प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और साप्ताहिक जनसुनवाई सत्र शुरू किए। यह वास्तविक समय में तकनीकी सहायता और शिकायत निवारण प्रदान करते हैं।

इस प्लेटफॉर्म ने उपभोक्ता विवादों को आगे बढ़ाने की लागत, समय और जटिलता को काफी हद तक कम कर दिया है, इससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाना

डिजिटल सुधारों के साथ-साथ, विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत संस्थागत क्षमता को मजबूत करना जारी रखा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ग्रुप 'ए' पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को दक्षता और प्रशासनिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया गया।

विभाग ने वर्ष के दौरान उपभोक्ता आयोगों, उद्योग निकायों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और शिक्षाविदों को शामिल करते हुए कई हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें भी आयोजित कीं। इन परामर्श बैठकों का मुख्य उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित ऑनलाइन व्यापार तौर-तरीकों और न्याय की त्वरित डिलीवरी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था।

उपभोक्ता आयोगों को सुदृढ़ करने की योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए राज्यों को 7.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई।

उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार

2025 में उपभोक्ता जागरूकता पहलों का ध्यान व्यापकता, समावेशिता और सभी तक पहुंच पर केंद्रित था। प्रमुख अभियान "जागो ग्राहक जागो" डिजिटल, प्रिंट और आउटडोर प्लेटफॉर्म पर लगातार चलता रहा। इसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, सुरक्षित उपभोग तौर-तरीकों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में शिक्षित किया गया।

स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट सुविधा से वंचित नागरिकों तक पहुंचने के लिए विभाग ने देशव्यापी आईवीआरएस वॉयस कॉल अभियान और 11 भाषाओं में एसएमएस के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया।

भारत की एआई पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्थित रूप से विकसित हो रहा है: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले प्रमुख उपलब्धियों की घोषणा की गई

एमईआईटीवाई ने 60 अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों के विचारों सहित एआई के भविष्य पर एक संकलन का विमोचन किया

(एजेंसी)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले एक उच्च स्तरीय संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने की। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अजय सूद और एमईआईटीवाई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। संवाददाता सम्मेलन में प्रमुख घटनाक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, वैश्विक

भागीदारी की पुष्टि की गई तथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के संभावित परिणामों की झलक दिखाई गई। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा जिसकी तैयारी चल रही है।

सभा को संबोधित करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है और यह वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बनने वाला है। उन्होंने एआई वैल्यू चेन में काम कर रहे उद्योगपतियों, डेवलपर्स एवं इनोवेटर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया मुलाकातों का उल्लेख किया, जिनमें मॉडल, एप्लिकेशन एवं अवसंरचना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों से भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थित प्रगति एवं तैनाती-आधारित समाधानों पर मजबूत ध्यान केंद्रीत होने का पता चलता है। मंत्री ने कहा कि प्रमुख आईटी कंपनियों ने 200 से अधिक विशिष्ट क्षेत्र-आधारित एआई मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान लॉन्च करने का प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा कि एआई अवसंरचना में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश पहले से ही हो रहा है, जो समिट के समापन तक दोगुना हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 500 विश्वविद्यालयों में एआई अवसंरचना एवं उद्योग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का विस्तार करके एआई प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे इस क्षेत्र के लिए एक मजबूत प्रतिभा तैयार

श्री अश्विनी वैष्णव ने "द इम्पैक्ट एजेंडाः लीडरशिप रिफ्लेक्शंस" नामक एक संकलन का भी विमोचन किया, जिसमें एआई के भविष्य तथा समावेशी विकास, नवाचार एवं सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर लगभग 60 प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों के विचार शामिल हैं।

वेवएक्स ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मीडिया, मनोरंजन और उभरती प्रौद्योगिकी में एआई समाधानों पर फोकस करेगा

वेवएक्स एआई स्टार्टअप के लिए बिजनेस नेटवर्किंग और प्रदर्शनी का मंच प्रदान करेगा

(एजेंसी)।

वेवएक्स ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए स्टार्टअप उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह समिट इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाधानों को प्रदर्शित करने और भारत के तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में काम करेगा।

समिट के हिस्से के तौर पर, वेवएक्स एक खास स्टार्टअप एग्जिबिशन प्रोग्राम आयोजित करेगा। इससे चुने हुए स्टार्टअप उद्यमों को अपने एआई-आधारित उत्पादों और समाधानों को देश-विदेश के अलग-अलग लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। एवीजीसी-एक्सआर सेगमेंट में काम करने वाले और एआई-आधारित उत्पादों पर काम कर रहे स्टार्टअप उद्यमों को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पवेलियन में खास शोकेस और बिजनेस नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पवेलियन मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में नवीनतम और उभरती हुई एआई प्रौद्योगिकी को दिखाने के लिए एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करेगा, जिससे इनोवेटर पॉलिसी बनाने

वालों, इंडस्ट्री की हस्तियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के साथ जुड़ सकेंगे, और सृजनात्मक और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

उम्मीद है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 स्टार्टअप उद्यमों और मुख्य हितधारकों के बीच व्यवस्थित जुड़ाव को बढ़ावा देकर भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

वेवएक्स के बारे में

वेवएक्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेव्स पहल के तहत एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया, मनोरंजन और भाषा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में इनोवेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत की अगली पीढ़ी के सृजनात्मक और प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया, वेवएक्स इनोवेटर, सरकारी संस्थानों और इंडस्ट्री की हस्तियों के बीच एक सेतु के रुप में काम करता है।

पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे के अंतर्गत संपर्क परियोजनाएं

(एजेंसी)।

अगरतला में दिसंबर, 2024 में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 72वीं पूर्ण बैठक के आयोजन के दौरान बनी सहमति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आठ उच्च-स्तरीय कार्य बलों का गठन किया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे (एनईईसी) पर एचएलटीएफ की अध्यक्षता मिजोरम के मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और असम, मेघालय और मणिपुर के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। एनईईसी पर एचएलटीएफ के जनादेश में, अन्य बातों के अलावा, एनईआर में मौजूदा आर्थिक बुनियादी ढांचे और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करना; कमियों की पहचान करना और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीतियां तैयार करना शामिल है। एनईईसी पर एचएलटीएफ की तीन बैठकें हो चुकी हैं।

'पीएम-डिवाइन' का व्यापक उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का तीव्र और समग्र विकास करना हैः

बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं

क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाएं

क्क्क क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को बढ़ाना, और

क् श. विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कमियों को भरना

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, योजना के अंतर्गत शुरूआत से लेकर 21 जनवरी 2026 तक कुल 48 परियोजनाओं के लिए 6044.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की

योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/आईएएस की होती है। हालांकि, परियोजनाओं की निगरानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्री तकनीकी सहायता इकाईयां, परियोजना गुणवत्ता निगरानी और थर्ड-पार्टी टेक्निकल इंस्पेक्शन एजेंसियों के माध्यम से और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के साथ-साथ समीक्षा बैठकों के दौरान भी की जाती है। उपरोक्त एजेंसियों की निरीक्षण रिपोर्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल पर परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी के लिए अपलोड की जाती है। ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, एफटीएसयू आईएएस के साथ मिलकर काम करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर परियोजना की प्रगति को अपडेट करते हैं।

'जिलों के सर्वांगीण विकास' थीम पर नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज 2025-26 का 34वां वेबिनार

नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज 2025-26 का 34वां वेबिनार 'जिलों के सर्वांगीण विकास' थीम पर 30 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा किया गया और उन्हें दोहराने पर चर्चा हुई

गुमला जिले की पहल, पूर्वी सिंहभूम पर कर्ण सत्यार्थी और कारगिल जिले की पहल, लद्दाख पर श्रीकांत बालासाहेब सुसे ने राष्ट्र के दर्शकों के सामने प्रस्तुति दी

प्रविष्टि तिथिः 30 खअठ 2026 5:31ढट्ु८ ढक्ष ऊै

प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पिछले विजेताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि उनका और भी अधिक प्रचार-प्रसार और दोहराव हो सके।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, डीएआरपीजी ने अप्रैल, 2022 से हर

महीने एक वेबिनार के हिसाब से 34 नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार आयोजित किए हैं, ताकि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकन का प्रचार-प्रसार और दोहराव को बढ़ावा दिया जा सके। हर वेबिनार में लाइन विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी शामिल होते हैं।

ये वेबिनार न सिर्फ पहल के संस्थागतकरण/स्थिरता की मौजूदा स्थिति बताते हैं, बल्कि इसके दोहराव/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी देते हैं।

34वां वेबिनार 30 जनवरी, 2026 को हुआ, जिसमें 2023 के लिए 'जिलों के समग्र विकास' थीम के तहत प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पावर पॉइंट प्रस्तुति दीः

गुमला जिला पहल, झारखंड, जिसे कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड ने प्रस्तुत किया; और

कारगिल जिला पहल, लद्दाख, जिसे श्रीकांत बालासाहेब सुसे, उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर ने प्रस्तुत किया।

वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के अपर सचिव पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में पूरे भारत में 600 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिले के अधिकारियों, केंद्र और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

ठाकुरगंज के कैम्पबेल रोड पर नियमों की उड़ी धज्जियां, ग्लोब कैफे बना अराजक तत्वों का अड्डा

लखनऊ (एजेंसी)।

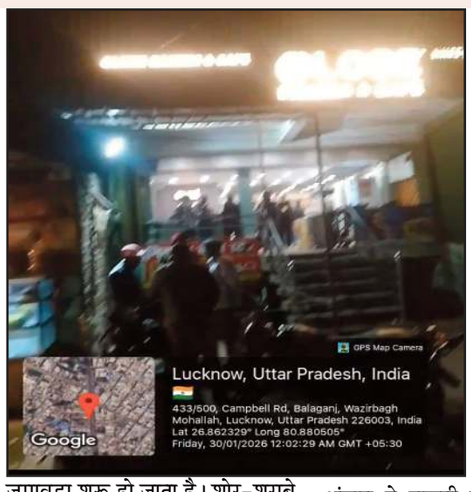

लखनऊ। राजधानी के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र अंतर्गत कैम्पबेल रोड इन दिनों सुरक्षा और शांति के लिहाज से चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों के मुताबिक, क्षेत्र में स्थित ग्लोब कैफे (ग्लोब कैफे) पर देर रात तक अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। देर रात तक सजती है महफिल, प्रशासन बेखबर नियमों को ताक पर रखकर कैम्पबेल रोड पर स्थित 'ग्लोब कैफे' देर रात तक संचालित होता हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात ढलते ही यहाँ संदिग्ध और अराजक तत्वों का

जमावड़ा शुरू हो जाता है। शोर-शराबे और हुड़दंग के कारण आसपास रहने वाले नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है। एक बड़े हादसे को दावत दे रही है 'खामोशी' क्षेत्रीय जनता का कहना है कि इन दुकानों पर जुटने वाली भीड़ अक्सर विवादों का कारण बनती है। अराजक तत्वों की मौजूदगी से यहाँ कभी भी कोई गंभीर वारदात को अंजाम दे सकती है बावजूद इसके, स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन साधे हुए है। प्रशासन की ढील के कारण इन कैफे संचालकों के हौसले बुलंद हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ कोई बड़ी घटना घट सकती है। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में पुलिस गश्त के दावों के बीच, कैम्पबेल रोड पर आधी रात के बाद तक दुकानों का खुला रहना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या स्थानीय पुलिस को इस जमावड़े की जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद लखनऊ पुलिस और जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा।

पीलीभीत में कुष्ठ रोग मुक्त अभियान: बीसलपुर सीएचसी में स्टाफ ने ली शपथ

(एजेंसी)।

पीलीभीत/ बीसलपुर विकसित भारत अभियान के तहत जिले को कुष्ठ रोग से पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और समस्त जनपदवासी मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुष्ठ रोग की जल्दी पहचान और इलाज संभव होने पर जोर देते हुए डीएम ने सभी संसाधनों का उपयोग करने का ऐलान किया।बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज इस अभियान का शुभारंभ हुआ। यहां जिलाधिकारी के संदेश के अनुरूप समस्त डॉक्टरों व स्टाफ ने शपथ ग्रहण की। शपथ समारोह में कुष्ठ प्रभावितों से भेदभाव समाप्त करने, उनके कलंक को दूर करने और समाज की मुख्यधारा में लाने का संकल्प लिया गया। सभी ने "भेदभाव समाप्त कर गरिमा सुनिश्चित करें" की प्रतिज्ञा के साथ शून्य सहिष्णुता का वादा किया।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुष्ठ रोगी और उनके परिवार के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर इस दिशा में पूर्ण योगदान देने का आह्वान किया गया।

माध्यमिक शिक्षकों का अंग्रेजी विषय प्रशिक्षण संपन्न, 110 शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित

फरीदपुर (बरेली)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) फरीदपुर, बरेली में माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत सभी प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

गौरतलब है कि शासन की योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय का विषयगत प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जाना था। इसी क्रम में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंग्रेजी विषय के कुल 110 शिक्षक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान डायट प्राचार्य दीप्ति वार्ष्णेय ने शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान और नवीन शिक्षण विधियों को विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज कुमार ने भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास का आधार भी है।

डायट प्रवक्ता एवं प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्रीकांत मिश्रा ने शिक्षकों को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना (छरफ्ह) कौशल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया में गतिविधि-आधारित पद्धति को अनिवार्य रूप से शामिल करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर बृजेश कुमार शर्मा ने पाठ योजना निर्माण की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की। मथुरा प्रसाद वर्मा ने अंग्रेजी कविता की पाठ योजना तैयार करने के तरीकों की जानकारी दी। अजीत कुमार शर्मा ने गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाने की विधियां बताईं, जबकि रामेंद्र कुमार गंगवार ने प्रभावी प्रश्न निर्माण की तकनीकों से शिक्षकों को अवगत कराया।

समापन सत्र का संचालन डायट प्रवक्ता श्रीकांत मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण से शिक्षकों में उत्साह देखा गया और उन्होंने इसे अपने शिक्षण कार्य में उपयोगी बताया।

विद्यालय में घटिया सामग्री से निर्माण, भ्रष्टाचार का आरोप; शिकायत बस्ते में धूल खा रही

(एजेंसी)।

पीलीभीत के बीसलपुर विकास क्षेत्र के जसकरनापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बड़े फंड के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और हेड टीचर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है।ग्रामीणों ने खुलासा किया कि निर्माण में खराब क्वालिटी का सीमेंट, दोमई ईंटें और सरिया इस्तेमाल हो रहा है। एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "काफी फंड आता है, लेकिन पूरा खर्च नहीं होता। बचा पैसा गोलमाल से हड़प लिया जाता है। हेड टीचर की भी जिम्मेदारी है, फिर भी

उच्च गुणवत्ता का काम नहीं हो रहा।" इसके अलावा, स्कूल के पेड़ बिना अनुमति काट दिए गए, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।मेंटेनेंस फंड पर सवाल

स्कूलों को रखरखाव के लिए अलग फंड मिलता है, लेकिन इसका हिसाब-किताब पारदर्शी नहीं। निर्माण में ही घटिया सामग्री लग रही है, तो रखरखाव का क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी इमारत की उम्र 5-10 साल से ज्यादा नहीं रहेगी, जो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है।शिकायत बस्ते में पड़ी, एबीएसए का आश्वासन अधूरा

शिकायतकर्ता ने 22 जनवरी 2026 को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) हर्षित शर्मा को शिकायत दर्ज की (शिकायत संख्या: 40015126001552)। शिकायत में लिखा है- "बीसलपुर के ग्राम जसकरनापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रहे घटिया सामग्री से निर्माण कार्य, दोम ईंट से कराया जा रहा। मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार, उच्च अधिकारी द्वारा कब कार्रवाई होगी? ऐसे टीचरों पर कार्रवाई कब?"

एबीएसए ने फोन पर निरीक्षण और कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन शिकायत अभी बस्ते में धूल खा रही है। ग्रामीण अब सवाल उठा रहे हैं कि वादा कब पूरा होगा ?ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई अप्रिय घटना हुई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

शारदा नदी का कहर: धनाराघाट पेंटून पुल जलमग्न

(एजेंसी)।

पीलीभीत,जिला मुख्यालय से डेढ़ लाख लोगों का संपर्क कटापीलीभीत, 30 जनवरी 2026: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शारदा नदी को फिर से उफान पर ला दिया है। गुरुवार रात से नदी का जलस्तर अचानक चढ़ने लगा, जिसके चलते धनाराघाट पर स्थित महत्वपूर्ण पेंटून पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया। इस पुल के मुख्य मार्ग पर नदी का पानी तेज बहाव के साथ चढ़ आया, जिससे जिला मुख्यालय से शारदा नदी के पार बसे लगभग एक दर्जन गांवों की डेढ़ लाख से अधिक आबादी का सीधा संपर्क कट गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मार्ग को वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए बंद कर दिया है।

शुक्रवार सुबह 10 बजे तक स्थिति और गंभीर हो गई, जब सड़क पर घुटने से अधिक ऊंचाई तक पानी भर गया। पेंटून पुल पर तैनात मुंशी बबलू मांझी ने बताया, "गुरुवार रात 8 बजे से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गई। सुबह होते ही पुल की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह डूब गया। हमने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोक दिया है और जलस्तर कम होने तक किसी को पार न करने की सख्त हिदायत दी है।" मांझी के अनुसार, नदी का जलस्तर सामान्य से 4 फीट ऊपर पहुंच चुका है, जो पिछले वर्षों

की तुलना में अधिक खतरनाक है।

इस पुल के बंद होने से शारदा पार के गामों जैसे अमरिया, खमरिया, सतिया आदि में रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला मुख्यालय और पूरनपुर तहसील से जुड़ने का यह एकमात्र सीधा मार्ग था। अब किसानों को अपनी उपज बाजार ले जाने, छात्रों को स्कूल पहुंचने और व्यापारियों को दैनिक कार्यों के लिए 20-25 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। विशेष रूप से बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह संकट गंभीर है। स्थानीय निवासी रामस्वरूप ने बताया, "मेरा पोता जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पहुंचने के लिए अब पूरनपुर होकर लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा। ऐसी स्थिति हर मानसून में दोहराई जाती है।

"क्षेत्रीय जनता लंबे समय से पेंटून पुल की अस्थायी प्रकृति से परेशान है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से शारदा नदी पर 1.2 किलोमीटर लंबे स्थायी पक्के पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह पुल अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा, लेकिन तब तक मौसमी बाढ़ से ग्रामीणों को जूझना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने राहत के इंतजाम किए हैं, जिसमें वैकल्पिक मार्गों पर यातायात नियंत्रण और जरूरी वाहनों को पास जारी करना शामिल है। साथ ही, सिंचाई विभाग की टीम नदी के जलस्तर पर नजर रख रही है।

स्थानीय विधायक और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि आपातकालीन नाव सेवा शुरू की जाए और प्रभावित गांवों में राशन व दवाओं का वितरण सुनिश्चित हो। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे शारदा जैसी नदियां बार-बार उफान पर आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

डीआईजी/एसपी के निर्देशन में मिशन शक्ति-5 अभियान तेज

(एजेंसी)।

पीलीभीत। उक्क्रृरढ पीलीभीत के निर्देशन में मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिला थाना पुलिस टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमण के दौरान छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों और साइबर आपराधों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

जागरूकता का प्रभाव

इस अभियान से छात्राओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पुलिस टीम ने महिलाओं के अधिकारों,

हेल्पलाइन नंबरों और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपाय सुझाए। यह प्रयास पीलीभीत पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निरंतर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा है।

अभियान का उद्देश्य

मिशन शक्ति-5 का लक्ष्य महिलाओं व बालिकाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन प्रदान करना है। थाना स्तर पर भ्रमण और जागरूकता सत्र आयोजित कर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाई जा रही है। इससे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

केजीएमयू : छात्रा यौन शोषण: निकाह गवाह पीलीभीत से दबोचा

लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डॉ. रमीज मलिक केस में ठइह पर सारिक खान गिरफ्तार; स्थानीय डॉक्टरों पर भी शक

(एजेंसी)।

पीलीभीत। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (ङ्क्षठ्व) की छात्रा के यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में लखनऊ पुलिस ने पीलीभीत से निकाह के गवाह को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट (ठइह) जारी होने के बाद चौक कोतवाली पुलिस ने स्थानीय सहयोग से मोहल्ला पंजाबियान निवासी सारिक खान पुत्र अजहर खान को उसके घर से दबोच लिया।

मामला पिछले साल दिसंबर का है। ङ्क्षठ्व छात्रा ने रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था। जांच में डॉ. रमीज गिरफ्तार हो चुका है। पता चला कि आरोपी ने अपनी पहली पत्नी का भी धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह किया था,जिसमें सारिक ने गवाह की भूमिका निभाई। निकाह शहर के एक काजी ने कराया था।

बृहस्पतिवार शाम लखनऊ पुलिस पीलीभीत पहुंची और शहर कोतवाली के सहयोग से छापा मारा। शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया, "कोर्ट वारंट पर कार्रवाई की गई। आरोपी को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लखनऊ ले जाया गया।" डॉ. रमीज मूल रूप से पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस उसके पैतृक घर पर पहले भी नोटिस चस्पा कर चुकी है।

जांच में सामने आया कि इस केस में स्थानीय कई डॉक्टर और लोग आरोपी की मदद कर रहे थे। पुलिस अब काजी और अन्य आरोपियों पर नजर रखे हुए है। सारिक से पूछताछ में और सुराग मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है।

भाकियू भानु का जनसम्पर्क अभियान तेज, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति से संगठन को मिली मजबूती

(एजेंसी)।

पीलीभीत जनपद में भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा चलाया जा रहा जनसम्पर्क एवं जागरूकता अभियान निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है। बीसलपुर तहसील अध्यक्ष महेन्द्र पाल गंगवार (पूर्व सैनिक) तहसील मीडिया प्रभारी दीनदयाल शास्त्री एवं बिलसंडा ब्लॉक अध्यक्ष राकेश प्रताप यादव के नेतृत्व में संगठन किसानों के बीच सक्रियता से कार्य कर रहा है।संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से

पदाधिकारियों द्वारा नई नियुक्तियां की गईं। राम भजन को बिलसंडा ब्लॉक संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही विशाल मिश्रा को बिलसंडा नगर अध्यक्ष, सचिन वर्मा को नगर उपाध्यक्ष तथा पवन वर्मा को नगर संगठन मंत्री के पद पर मनोनीत किया गया।नव नियुक्त पदाधिकारियों के जुड़ने से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और कार्यकताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी को बधाई देते हुए किसान हितों की रक्षा एवं संगठन की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की।भाकियू भानु का यह अभियान क्षेत्र में संगठन की प्रगति एवं किसानों की समस्याओं को लेकर सजग प्रयासों का प्रतीक बनता जा रहा है।

पैंतबोझी में गणतंत्र दिवस पर नहीं लहराया तिरंगा, शासन के आदेशों की खुली अवहेलना

पीलीभीत(बिलसंडा)-जहाँ एक ओर पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवमयी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, वहीं जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा की ग्राम पंचायत पैंतबोझी से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ ग्राम पंचायत सचिवालय पर राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ध्वजारोहण नहीं किया गया, जो वर्तमान सरकार के कड़े शासनादेशों और राष्ट्रीय मयार्दा का खुला उल्लंघन माना जा रहा है।

मुख्य घटनाक्रम: सूना रहा पंचायत सचिवालय

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, 26 जनवरी की सुबह जब अन्य सरकारी संस्थानों पर आन-बान-शान के साथ तिरंगा फहराया जा रहा था, तब पैंतबोझी ग्राम पंचायत सचिवालय का परिसर सूना पड़ा था। ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते यहाँ ध्वजारोहण की रस्म तक अदा नहीं

की गई।

शासन के आदेशों की अनदेखी

पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस से पूर्व समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी और अर्धसरकारी भवनों पर प्रातः 8:30 बजे ध्वजारोहण अनिवार्य रूप से किया जाए। पैंतबोझी में इस आदेश की अनदेखी न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अवमानना की श्रेणी में आती है।

ग्रामीणों में आक्रोश और जवाबदेही की माँग-इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि:

राष्ट्रीय पर्व का अपमान: यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के प्रतीक का अपमान है।

अधिकारियों की मनमानी: ग्राम विकास में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों का इस तरह का रवैया उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है।

कड़ी कार्रवाई की माँग: ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से माँग की है कि संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी और लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय जाँच कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

क्या कहते हैं नियम?

भारतीय ध्वज संहिता और उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय पर्वों पर सार्वजनिक भवनों पर ससम्मान ध्वजारोहण करना संबंधित अधिकारी की संवैधानिक जिम्मेदारी है। देशभक्ति और अनुशासन के इस पर्व पर ऐसी घटनाएं प्रशासन की छवि को धूमिल करती हैं। अब देखना यह होगा कि जनपद के उच्चाधिकारी इस गंभीर विषय पर क्या एक्शन लेते हैं ताकि भविष्य में पैंतबोझी जैसी पुनरावृत्ति किसी अन्य पंचायत में न हो।